

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: ०९ अगस्त, 2016

विषय:-ज्ञान ज्योति ट्रस्ट, हरिद्वार को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ (महाविद्यालय की स्थापना) हेतु ग्राम अकबरपुर ऊद, तहसील लक्सर, जनपद हरिद्वार में 1.0520 है० भूमि कय की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या-1360/जिला भूमि व्यव०-2014 दिनांक-27.01.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, ज्ञान ज्योति ट्रस्ट, हरिद्वार को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ (महाविद्यालय की स्थापना) हेतु ग्राम अकबरपुर ऊद, तहसील लक्सर, जनपद हरिद्वार के खाता संख्या-46 के खसरा संख्या-38, रकबा 1.0520 है० भूमि कय की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(III) के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं :-

1. क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।
2. क्रेता द्वारा कय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (पॉलिटेक्निक, अस्पताल, विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान की स्थापना) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग, जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।
3. जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

4. जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।
5. शासन द्वारा दी गई भूमि कय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।
6. ईकाई का द्वारा कय की जानी वाली भूमि का उपयोग मात्र शैक्षणिक प्रयोजन (महाविद्यालय की स्थापना) हेतु किया जायेगा।
7. सम्बन्धित ट्रस्ट को भूमि पर निर्माण कराये जाने से पूर्व स्थल का भू-उपयोग कृषि से सामुदायिक सुविधायें (महाविद्यालय) में परिवर्तन कराना होगा।
8. स्थल पर निर्माण प्रचलित उपविधि के अनुसार किया जायेगा तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार पहुंच मार्ग उपलब्ध कराया जायेगा।
9. शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निर्माण का प्लान सीडा/विनियमित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराना आवश्यक होगा।
10. जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि भूमि के प्रस्तावित अन्तरण से किसी राजस्व नियमों का उल्लंघन न हो तथा भूमि भारमुक्त एवं विवाद रहित हो। भूमि के भारमुक्त होने व विवाद रहित होने पर ही विक्रय अनुमन्य होगा।
11. सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।
12. किसी भी दशा में क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो, इसके लिए भूमि कय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।
13. भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
14. योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।
15. ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के संचालन से पूर्व सम्बन्धित विभागों से मान्यता/अनापत्ति प्राप्त कर ली जायेगी।
16. सम्बन्धित इकाई द्वारा प्रस्तावित योजना को प्रारम्भ करने से पूर्व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन0जी0टी0) से शून्य आधारित (Zero based) अनापत्ति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
17. सम्बन्धित इकाई द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट) के अन्तर्गत जैविक व अजैविक पदार्थों का प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा।

18. सम्बन्धित इकाई द्वारा जलोत्सारण (सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट) हेतु निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
19. जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित भूमि के मध्य व किनारे चैक रोड़, नाला तथा राज्य सरकार की अवशेष भूमि आदि होने अथवा न होने की स्पष्ट सूचना/विवरण शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
20. इकाई द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
21. आवेदक द्वारा स्थापित किये जाने वाले संस्थानों में उत्तराखण्ड मूल के निवासियों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक को नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
22. उपरोक्त किसी भी शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश के अनुपालन स्थिति से भी शासन को यथासमय अवगत कराने का कष्ट करें।

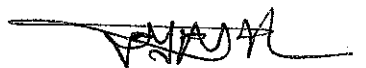
भवदीय,

(डी०एस० गब्र्याल)
सचिव।

पू०प०सं०-१४१४/XVIII(II)/2016-01(50)/2014/समदिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. श्री संदीप चौधरी, अध्यक्ष, ज्ञान ज्योति ट्रस्ट, मकान नं०-10 अनमोल भवन, बालसन इन्केव, कनखल, हरिद्वार।
5. निदेशक एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
6. प्रभारी, मीडिया केन्द्र उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,


(जे०पी० जोशी)
अपर सचिव।